Government of India
Ministryof Drinking Water & Sanitation

Subject: Monthly summary for the month of **May, 2018** in respect of Ministry of Drinking Water and Sanitation

As of May 31st, under the Swachh Bharat Mission (Grameen), over 7.4 crore toilets have been built across rural India. As an outcome, over 3.8 lakh villages and 390 districts have been declared Open Defecation Free (ODF), along with 17 States and Union Territories — Sikkim, Himachal Pradesh, Kerala, Haryana, Uttarakhand, Gujarat, Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Meghalaya, Mizoram, Punjab, Rajasthan, Maharashtra, Chandigarh, Daman & Diu, D & N Haveli and Andaman & Nicobar islands.

Capacity Building

Ministry of Drinking Water and Sanitation organised a workshop on ODF Sustainability on 16th May and 17th May, 2018 at YASHADA, Pune. 120 ACSs/Principal Secretaries/Mission Directors/State Coordinators/ Collectors/ CEOs, ZP participated in the Workshop. The main issues discussed were ODF sustainability, Water for Sanitation, IEC for ODF-S, Monitoring etc., the States/Districts presented success stories as well.

On 17th May, 2018, a field visit to Panderewari Gram Panchayat of Pune district was organized. Secretary (DWS), along with the Comptroller and Auditor General of India, undertook pit emptying exercise. ACSs/ Principal Secretaries/ Mission Directors/ State Coordinators /Collectors/CEOs, ZP also participated in the exercise.

Integrated Management Information System (IMIS) Consultative Workshop with Uttar Pradesh

A consultative workshop on IMIS was conducted with district consultants of Uttar Pradesh. The workshop was chaired by the Secretary and attended by the Additional Chief Secretary and Mission Director of Uttar Pradesh SBM (G). The workshop discussed the issues faced by the consultants in the districts and the assistance required to enable the progress of the state to improve. Feedback was given by the Additional Chief Secretary and Mission Director for facilitating data entry into the IMIS.

Workshop on Toilet Technology

A Workshop on Toilet Technology was organized at New Delhi on 27th May, 2018. Around 60 ACS/Principal Secretaries/State Coordinators/Collectors/CEOs, ZP participated in the workshop. On this occasion, a video spot on Twin Pit toilet technology featuring Shri Akshay Kumar, Producer and Actor was launched. Shri Akshay Kumar also interacted with the participants.

Coordination with KRCs

Ministry of Drinking Water and Sanitation organized Consultation with Key Resource Centres (KRCs) on 25th May, 2018 at New Delhi. Around 26 KRCs and 4 SIRDs/ATIs attended. State Coordinators/Consultants from some States also attended the Workshop. In the meeting, the KRCs and States provided feedback on trainings. Way-forward for capacity building was also discussed in detail.

Swachhata Action Plan (SAP)

The yearly review meeting for the Swachhata Action Plans (2018-19) of various Ministries was held with the Committee of Secretaries, chaired by the Cabinet Secretary, followed by a workshop for SAP Nodal officers on 11 May 2018.

Monitoring and Review of SBM-G

Swachh Bharat Mission (Grameen) progress was reviewed in many States during the month of May through a combination of physical visits and video conferences: The following field visits were undertaken and review meeting were conducted with the State SBM team :

1	Telangana	1-May-18
2	Manipur and Nagaland	9 and 10 May 2018
3	Madhya Pradesh	12-May-18
4	Odisha	24-May-18
5	Maharashtra	31-May-18

Video Conference:

2. Weekly video conferences with Zila Swachh Bharat Preraks were held on 19 May 2018 and 26 May 2018, for review and the way forward.

National Rural Drinking Water Program (NRDWP)

A review meeting was held in the presence of Principal Secretary to Prime Minister on 5 May 2018. The meeting discussed the status of current schemes initiated under the program and the challenges faced by the Ministry in implementation of these schemes.

A Video Conference was held to review the pace of expenditure under various components of NDRWP including the National Water Quality Sub-Mission (NWQSM) and RWSSP-LIS, with all States (except Gujarat, Himachal Pradesh, Kerala, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Uttarakhand, Meghalaya and Nagaland), on 30th May 2018.

Swajal

A proposal has been made towards the implementation of ‘Swajal — an alternate, demand driven and community center approach, to provide sustainable and sufficient access

to drinking water in rural areas in the 117 aspiration districts. The same has been discussed with NITI Aayog.

15th Finance Commission

A presentation was made by Secretary, DWS to the 15th Finance Commission, on 14 May 2018, towards the prioritisation of the Water, Sanitation and Hygiene (WASH) sector in the Commission's final report for October 2019

***

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

विषयः पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से संबंधित मई, 2018 माह हेतु मासिक सार

31 मई के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत, पूरे भारत में 7.4 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। परिणाम के अनुसार, 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों- सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के साथ 3.8 लाख से अधिक गांवों और 390 जिलों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है।

<u>क्षमता निर्माण</u>

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 16 मई और 17 मई, 2018 को याशदा पुणे में ओडीएफ स्थायित्व पर एक कार्यशाला आयोजित की। 120 एसीएस/ मुख्य सचिवों/ मिशन निदेशकों/ राज्य समन्वयकों/ कलेक्टरों/ सीईओ, जिला परिषदों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। चर्चा किए गए मुख्य मुद्दों में ओडीएफ स्थायित्व, स्वच्छता हेतु जल, ओडीएफ-एस हेतु आईईसी, मॉनीटरिंग आदि थे। राज्यों/ जिलों ने सफलता की कहानियां भी प्रस्तुत कीं।

पुणे जिला के पांडेरेवाड़ी ग्राम पंचायत में दिनांक 17 मई, 2018 को कार्य क्षेत्र दौरा आयोजित किया गया। सचिव (डीडब्ल्यूएस) ने भारत के महानियंत्रक व लेखा परीक्षक के साथ पीट् खाली करने का कार्य सम्पन्न किया। एसीएस/ मुख्य सचिवों/ मिशन निदेशकों/ राज्य समन्वयकों/ कलेक्टरों/ सीईओ, जिला परिषदों ने इस कार्य में भाग लिया।

<u>उत्तर प्रदेश के साथ एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) परामर्शी कार्यशाला</u>

आईएमआईएस पर एक परामर्शी कार्यशाला का आयोजन उत्तर प्रदेश के जिला परामर्शकों के साथ किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता सचिव द्वारा की गयी और इसमें उत्तर प्रदेश एसबीएम (जी) के अपर मुख्य सचिव और मिशन निदेशक ने भाग लिया। इस कार्यशाला में इन जिलों में परामर्शकों द्वारा सामना किए जा रहे विषयों और अपेक्षित सहायता पर चर्चा की गईं ताकि राज्य की प्रगति बढ़ायी जा सके। आईएमआईएस में डाटा एंट्री को सुसाध्य बनाने हेतु अपर मुख्य सचिव और मिशन निदेशक द्वारा फीडबैक दिए गए।

शौचालय प्रौद्योगिकी पर कार्यशाला

दिनांक 27 मई, 2018 को नई दिल्ली में शौचालय प्रौद्योगिकी पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में लगभग 60 एसीएस/ मुख्य सचिवों/ राज्य के समन्वयकों/ कलेक्टरों/ सीईओ, जिला परिषदों ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री अक्षय कुमार, निर्माता एवं अभिनेता को प्रदर्शित करते हुए दो गड्डे वाले शौचालय प्रौद्योगिकी पर एक विडियो स्पॉट को भी प्रारंभ किया गया। श्री अक्षय कुमार ने प्रतिभागियों के साथ भी बातचीत की।

मुख्य संसाधन केन्द्रों (केआरसी) के साथ समन्वय

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 25 मई, 2018 को नई दिल्ली में मुख्य संसाधन केंद्रों (केआरसी) के साथ वार्ता आयोजित की। लगभग 26 केआरसी और 4 एसआईआरडी/ एटीआई ने इस बैठक में भाग लिया। कुछ राज्यों के राज्य समन्वयकों/ परामर्शकों ने भी इस कार्यशाला में भाग लिया। इस बैठक में, केआरसी और राज्यों ने प्रशिक्षणों पर फीडबैक दिए। क्षमता निर्माण हेतु भावी-कार्यनीति पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

स्वच्छता कार्रवाई योजना (सैप)

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न मंत्रालयों की स्वच्छता कार्रवाई योजना (2018-19) हेतु वार्षिक समीक्षा, सचिवों की समिति के साथ आयोजित की गई जिसके बाद 11 मई, 2018 को सैप नॉडल अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई।

एसबीएम-जी की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा

मई माह के दौरान कार्य स्थलों के दौरों और विडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से कई राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा की गई। निम्नलिखित कार्य स्थल के दौरे किए गए और राज्य की एसबीएम टीम के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गईः

1.	तेलंगाना	1 मई, 2018
2.	मणिपुर व नागालैंड	9 मई और 10 मई, 2018
3.	मध्य प्रदेश	12 मई, 2018
4.	ओडिशा	24 मई, 2018
5.	महाराष्ट्र	31 मई, 2018

विडियो कॉन्फ्रेंस

2. समीक्षा और भावी कार्यनीति हेतु 19 मई, 2018 और 26 मई, 2018 को जिला स्वच्छ भारत प्रेरकों के साथ सप्ताहिक विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।

<u>राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)</u>

प्रधान मंत्री के मुख्य सचिव की उपस्थिति में 5 मई, 2018 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की गई वर्तमान योजनाओं की स्थिति और इन योजनाओं के क्रियान्वयन में मंत्रालय द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों पर चर्चा की गई।

एनआरडीडब्ल्यूपी के विभिन्न घटकों जिनमें राष्ट्रीय जल गुणत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) और आरडब्ल्यूएसएसपी- एलआईएस शामिल हैं, सभी राज्यों के साथ (गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, मेघालय और नागालैंड को छोड़कर) 30 मई, 2018 को व्यय की गति की समीक्षा करने हेतु एक विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।

<u>स्वजल</u>

स्वजल- एक वैकल्पिक, मांग चालित और सामुदायिक केन्द्रित अवधारणा के क्रियान्वयन हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया गया है ताकि 117 आकांक्षी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थायी और पर्याप्त पहुंच उपलब्ध कराई जा सके। इन मुद्दों पर नीति आयोग के साथ भी चर्चा की गई।

<u>15वां वित्त आयोग</u>

अक्टूबर, 2019 की आयोग की अंतिम रिपोर्ट में जल, स्वच्छता और हाइजीन (वॉश) की प्राथमिकता हेतु सचिव, डीडब्ल्यूएस द्वारा 14 मई, 2018 को 15वां वित्त आयोग के समक्ष एक प्रस्तुति दी गई।

******